3.	Sports Project Development Area (SFDA)	Three SPDA Centres at Rajkot, Patan and Devgarh Baria have been established where children between age group of 9-14 are given training in various sports disciplines. The scheme is implemented in collaboration with the State Government.
4.	Special Area Games Scheme (SAG)	One SAG Centre is established in Gujarat at Gandhi Nagar. SAI bears entire expenditure to select children, who are provided in-house training facilities alongwith educational and vocational facilities.

In addition to the above SAI has established a Regional Centre at Gandhi Nagar to ensure effective implementation of various schemes in the States of Gujarat, Maharashtra, Goa and UTs of Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli. This Centre also conducts diploma courses in coaching in the disciplines of cricket, volley ball, hockey, kho-kho, swimming, hand ball and athletics.

सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संगठनों के लिये वैधानिक दर्जा

1622. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी सहायता प्राप्त बाल स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड और केन्द्रीय तकनीकी समिति आदि को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इनके वार्षिक व्यय की लेखा परीक्षा की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) केन्द्रीय तकनीकी समिति द्वारा गुजरात में कौन-कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वास राजेश्वरी) : (क) केन्द्रीय तकनीकी समिति को कानूनी दर्जा देने के संबंध में, फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है । बाल स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड को कोई सहायता नही दी जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी, नहीं । केन्द्रीय तकनीकी समिति, 1976 में इसके गठन के समय से ही, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का एक हिस्सा थी । तदनुसार, केन्द्रीय तकनीकी समिति के लेखाओं की लेखा परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली के माध्यम से केन्द्रीय राजस्व, लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती थी । केन्द्रीय तकनीकी समिति के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से बाहर अंतरण के परिणामस्वरूप, इसे केन्द्रीय राजस्व लेखा-परीक्षा निदेशालय की सेवाएं उपलब्ध न हो सकीं । उक्त निदेशालय से यह अनुरोध किया गया है कि वह वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय तकनीकी समिति के लेखाओं की लेखा-परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर करें ।

(ङ) केन्द्रीय तकनीकी समिति आजकल, गुजरात राज्य के 18 जिलों में समेकित बाल विकास सेवा की 137 परियोजनाओं में स्वास्थ्य एवं पोषाहार घटक के प्रबोधन के साथ-साथ समेकित बाल विकास सेवा क्षेत्रों में सेवा-इतर क्षेत्रों की तुलना में स्वास्थ्य और पोषाहार

सेवाओं के प्रभाव का अभिनिर्धारण करने हेतु राज्य में वार्षिक सर्वेक्षण करने में संलग्न है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय तकनीकी समिति, समाज कल्याण क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं तथा चिकित्सा अधिकारियों/सलाहकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है । वर्ष 1993-94 के दौरान, केन्द्रीय तकनीकी समिति द्वारा गुजरात राज्य में 22 पाठ्यक्रम आयोजित करके कुल 506 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया ।

गुजरात में ऐतिहासिक स्मारकों के रख-रखाव पर किया गया व्यय

1623. श्रीमति उर्मिला चिमनभाई पटेल :
श्रीमती आनन्दीबेन जैठाभाई पटेल:
क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1992-93 और 1993-94 के दौरान गुजरात में प्रत्येक ऐतिहासिक किले और स्मारक के संरक्षण, नवीकरण और रख-रखाव पर कितना धन खर्च किया गया ; और

(ख) वर्ष 1994-95 में इस कार्य के लिए कितना धन आबंटित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान, गुजरात राज्य के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों, जिनमें किले भी शामिल हैं, के रखरखाव, संरक्षण तथा परिरक्षण पर हुआ व्यय तथा 1994-95 के लिए किये जाने वाले खर्च का प्रावधान अनुबंध "क" पर दिया गया । [देखिए परिशिष्ट 171, अनुपत्र सं 31]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आधुनिकीकरण

1624. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं ;

(ग) इस समय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दी जा रही है ;

(घ) क्या सरकार अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध वृहत् साहित्य को विश्वविद्यालय द्वारा उर्दू में अनुवाद किए जाने को प्रोत्साहन देगी ; और

(ङ) विश्वविद्यालय की कितने मूल्य की संपत्ति का अतिक्रमण किया जा चुका है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार आयोग ने आठवीं योजना के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (अ० वि०) के विकास, विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 966.00 लाख रुपये आबंटित किये हैं । योजनागत अनुदान के अलावा आयोग के वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमश: 3603.60 लाख रु०, 4119.47 लाख रु० और 5628.09 लाख रु० के रखरखाव अनुदान भी जारी किए हैं । इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे विशेष सहायता कार्यक्रम, डी० डी०ए० सी०ए०एस० आदि भी जारी किए गए हैं ।

(ख) आठवीं योजना के प्रस्तावों को प्रतिपादित करते समय विश्वविद्यालय ने अन्य बातों के साथ-साथ महिला छात्र सुविधाओं सहित, छात्र सुविधाओं को ध्यान में रखा है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयोग द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय